

व्याज का ऋण-योग्य कोष सिद्धान्त या नव प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Loanable Funds Theory Or Neo-Classical Theory)

इस सिद्धान्त को उधार देय कोष सिद्धान्त भी कहा जाता है। यह सिद्धान्त स्वीडन के अर्थशास्त्री नट विकसेल (Knut Wicksell) द्वारा प्रतिपादित किया गया। Bertil Ohlin, Eric Lindahl और Gunnar Myrdal के द्वारा इस सिद्धान्त का सुधार हुआ रूप प्रस्तुत किया गया। Englund में इस सिद्धान्त का विकास Robertson के द्वारा किया गया।

Loanable Funds Theory, Classical Theory के ऊपर एक सुधार है। क्योंकि इसमें ऋण-योग्य कोषों की मांग और पूर्ति बावदी का प्रयोग अधिक विस्तृत अर्थ में किया गया है। इस सिद्धान्त में ऋण-योग्य कोषों की पूर्ति में केवल वर्तमान आय में से वृत्त को ही शामिल नहीं किया गया है बल्कि उद्योग बैंक सारन, विरंचय तथा अतिनियोग भी शामिल हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार ऋण-योग्य कोषों की मांग केवल विनियोग के कारण ही पैदा नहीं होती बल्कि वह धन को इकट्ठा करने की इच्छा के कारण भी होती है।

इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज ऋण-योग्य कोषों या विनियोग कोषों के लिए दिया जाता है। व्याज की दर उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ पर ऋण-योग्य कोषों की मांग और ऋण-योग्य कोषों की पूर्ति बराबर होती है।

ऋण-योग्य कोषों की मांग (Demand for Loanable Funds):  
Loanable Funds की मांग के चार प्रमुख स्रोत हैं:-

- (1) व्यापारियों तथा उत्पादकों के द्वारा मांग (Demand for Traders and Producers):- यह लोग ऋण-योग्य कोषों की मांग विनियोग के उद्देश्यों के लिए करते हैं। उन्हें अपने पुंजीगत उपकरणों के विस्तार तथा उनके सुधार के लिए पुंजी की जरूरत

होती है। वे पुंजीगत उपकरणों को खरीदने के लिए ऋण-योग्य कोषों की मांग करते हैं। वे व्याज की दर अधिक होने पर कम कोषों की मांग करेंगे तथा व्याज की दर कम होने पर उनके द्वारा अधिक कोषों की मांग की जायेगी।

(2) उपभोक्ताओं द्वारा मांग (Consumer's Demand for Loanable Funds): उपभोक्ताओं द्वारा ऋण-योग्य कोषों की मांग उपभोग योग्य विकास वस्तुओं को खरीदने के लिए की जाती है। यदि वे अपनी आय से अधिक माला में खर्च करने का निश्चय करते हैं तो वे ऋण-योग्य कोषों की मांग करेंगे। ऊँची व्याज की दर पर उपभोक्ताओं द्वारा कम माला में Loanable Funds की मांग की जायेगी तथा नीची व्याज की दर पर उनकी अधिक माला में मांग की जायेगी।

(3) सरकारी मांग (Government Demand): सरकार भी मुद्रा बाजार से रूपया उधार लेती है तथा काफी माला में ऋण-योग्य कोषों की मांग उत्पन्न करती है। नीची व्याज की दर पर सरकार अधिक माला में ऋण-योग्य कोषों की मांग करती है और ऊँची व्याज की दर पर मांग कम की जाती है।

मुद्रा काल, आर्थिक संकट या आर्थिक विकास के माल में सरकार की Loanable Funds की मांग व्याज की दर से प्रभावित नहीं होती।

(4) संजाल के लिए मांग (Demand for Hoarding):  
जब लोग ऋण-योग्य कोषों को नकद रूप में रखना चाहते हैं तो उसके कारण भी Loanable Funds की मांग होती है। जब व्याज की दर कम होती है तो लोग नकद रूप में रखने के लिए अधिक माला में Loanable Funds की मांग करते हैं। व्याज की दर अधिक होने पर वे कम माला में मांग करते हैं।

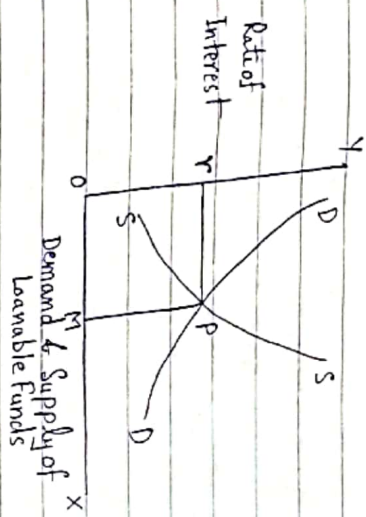
(1) ऋण-योग्य कोषों की पूर्ति (Supply of Loanable Funds) :-  
वचतों (Savings) :- वचतें Loanable Funds की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। Robertson के अनुसार लोग अपनी वर्तमान आय में से वचत नहीं करते बल्कि वे अपनी प्रयोग-योग्य आय (disposable income) में से वचत करते हैं, जो पिछली संप्रदाय-अवधि की आय होती है। व्याज की दर अधिक होने पर लोग अधिक वचतों को तथा कम देने पर उनके द्वारा कम मात्रा में वचत की जायेगी।

(2) बैंक सार्व (Bank Credit) :- बैंक सार्व Loanable Funds का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। बैंक व्यावसायियों को Loanable Funds प्रदान करते हैं क्योंकि उनके द्वारा सार्व का निर्माण किया जाता है जिसे वे विनियोग केलिए उधार देते हैं।

(3) पिछली वचतों का विसंचय (Disbarding of Past Savings) :- व्यक्ति तथा फर्म अपनी पिछली वचतों में से भी कोष निकाल सकती हैं। विसंचय का परिणाम ऋण-योग्य कोषों की पूर्ति को बढ़ाने का होता है। कच्ची व्याज की दर पर अधिक मात्रा में विसंचय किया जाता है और नीची व्याज की दर पर कम मात्रा में विसंचय किया जाता है।

(4) अविनियोग (Disinvestment) :- अविनियोग को विनिवेश भी कहते हैं। अविनियोग या विनिवेश का अर्थ यह नहीं है कि उद्योगपति चलता हुआ कारखाना बन्द कर दे लेकिन यदि उद्योग में किसी नयी तकनीक के आ जाने से मशीन पुरानी हो जाये और लाभ की आशाएं अधिक न हों तो उद्योगपति उस उद्योग को नई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बनाता और कारखाने को बेचकर उधार ली गई पूंजी का मुआताम कर देता है। इस स्थिति को विनिवेश कहा जा सकता है। किसी संप्रदाय बाजार में व्याज की दर अधिक होती है तो विनिवेश अधिक होता है और व्याज की दर कम हो तो विनिवेश कम होता है।

व्याज का निर्धारण (Determination of Interest) :-



व्याज की दर उस बिन्दु पर निर्धारित होगी जहां पर ऋण-योग्य कोषों की मांग उनकी पूर्ति के ठीक बराबर होती है। यदि ऋण-योग्य कोषों की मांग और पूर्ति में असंतुलन होता है तो व्याज की दर बदल जायेगी और वह अपने सन्तुलन बिन्दु को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी। Diagram में व्याज दर का निर्धारण बिन्दु P पर करते हुए बाजार व्याज दर को Or के बराबर निर्धारित करते हैं।

(1) आलोचना (Criticisms) :- ऋण-योग्य कोष सिद्धान्त Classical Theory of Interest के ऊपर एक सुधार है लेकिन फिर भी इसकी आलोचना निम्नलिखित आधार पर की गई है - प्रतिष्ठित सिद्धान्त की तरह यह सिद्धान्त भी आय के स्तर को स्थिर मानता है जो ठीक नहीं है। एक प्रतिस्तील समाज में आय हमेशा बढ़ती रहती है और उसका Loanable Funds की Supply पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। Keynes के अनुसार वचत व्याज की दर पर निर्भर नहीं होती बल्कि वह आय के स्तर के द्वारा निर्धारित होती है। वचत और विनियोग में समानता व्याज की दर के द्वारा निर्धारित न की जाकर आय के स्तर के द्वारा की जाती है।

(2) यह सिद्धान्त विनियोग के आय पर पड़ने वाले प्रभावों की उपेक्षा करता है। यह सिद्धान्त यह बताता है कि कच्ची व्याज की दर पर लोग अधिक वचत करते हैं लेकिन हमेशा श्रेष्ठा नहीं होता है।

ऊँची ब्याज की दर का प्रभाव विनियोग को कम करने का हो सकता है जिससे आय कम हो जायेगी और लोगों द्वारा कम बचत की जायेगी। इस प्रकार ऊँची ब्याज की दर का परिणाम हमेशा बचत को बढ़ाने वाला नहीं होता है। वह विनियोग की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर उसे कम भी कर सकती है।

(3)

अमरीकी अर्थशास्त्री Prof. Hansen ने बताया कि ऋण-योग्य कोष सिद्धान्त अनिर्धारणीय (indeterminable) है। यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि ब्याज की दर कैसे निर्धारित होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार ब्याज की दर Loanable Funds से निर्धारित होती है लेकिन Loanable Funds स्वयं व्यय-योग्य आय (disposable income) पर निर्भर करते हैं। व्यय-योग्य आय खुद निवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। निवेश की मात्रा खुद ब्याज की दर पर निर्भर करती है। इसलिए यह सिद्धान्त एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जिससे ब्याज दर का निर्धारण नहीं हो सकता।

